

रजिस्ट्री सं. डी-222

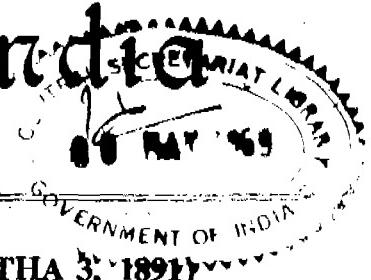
REGISTERED NO. D-222



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 21]

नई विल्सी, मानिषार, मई 24, 1969 (जेष्ठा 3, 1891)

No. 21]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 24, 1969 (JYAISHTHA 3, 1891)

इस भाग में सिव्वन पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असाधा संख्यान के क्षय में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखा भारत का असाधारण राजपत्र 22 अप्रैल 1969 तक प्रकाशित किया गया है :-

The undementioned *Gazette of India Extraordinary* was published up to the 22nd April 1969 :-

अक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
50	No. F.7/12/69-Estt.(C) dt. 15-4-69	Min. of Home Affairs.	Appointment of a Committee of Jurists to safeguard assurances to the people of the Telengana in the matter of employment in the public services.
51	No. 56-ITC(PN)/69, dt. 19-4-69	Min. of Foreign Trade & Supply.	Conditions for licensing Public sector imports of the value of Rs. 50,000/- or less under West German Commodity credit for 1968-69.
	No. 57-ITC(PN)/69 dt. 19-4-69	Do.	Errata (i) Import Policy for registered exporters for the year April/69-March/70 (Amendment No. 3).
52	No. 58-ITC(PN)/69 dt. 21-4-69	Do.	Import Policy for the year April/69-March/70 (Errata No. 1).
53	No. F.22/1/69-SR, dt. 22nd April/69	Min. of Home Affairs.	Appointment of a committee to determine the surplus relatable to Telengana to be spent on the development of Telegana region.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइसेंस, दिल्ली के नाम मांग-दर भेजने पर भेज दी जाएंगी।
मांग-दर प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, 'Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these *Gazettes*.

कित्ति-सूची (CONTENTS)

भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) पृष्ठ	भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मंत्रालय पृष्ठ को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	467	1971
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	553	189	
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	21	485	
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	487	191	
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—	57
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रबन्ध समितियों की रिपोर्ट	भाग III—खंड 4—विधिक नियमों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	—	265
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य लोग के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	1353	87	
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	PAGE	PAGE	
	467		867
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court			1971
	553		
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	21		189
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	487		485
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—		191
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—		57
PART II—SECTION 3.—Sub-Sec. (i)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1353		265
SUPPLEMENT No. 21— Weekly Epidemiological Reports for week- ending 17th May 1969			867
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 26th April 1969			881

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा संविवालय को छोड़कर) भारत सरकार के बनायालयों और उच्चस्त्र न्यायालय द्वारा जारी की गई विचित्र नियमों, विभिन्न मर्यादाओं तथा आदेशों और संकलनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 नवम्बर 1968

सं. 26-प्रेज/69—राष्ट्रपति डिफेंस सिक्योरिटी कोर मैडल प्रथम वर्ग तथा डिफेंस सिक्योरिटी कोर मैडल द्वितीय वर्ग का जिनका संस्थित किया जाना इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या 54-प्रेज/64, दिनांक 10 जुलाई, 1964 में अधिसूचित किया गया था, नाम बदल कर क्रमशः “उप्रक्रम रक्षा सुरक्षा कोर मैडल” तथा “रक्षा सुरक्षा कोर मैडल” करते हैं, और इस नियमित निम्नलिखित अध्यादेश बनाते तथा व्यवस्थापित एवं स्थापित करते हैं जो 18 नवम्बर, 1968 से प्रभावशील समझे जायेंगे:—

उप्रक्रम रक्षा सुरक्षा कोर मैडल

प्रथम—यह मैडल “उप्रक्रम रक्षा सुरक्षा कोर मैडल” कहा जायेगा (जिसे इसमें इसके पश्चात् मैडल कहा गया है)।

द्वितीय—मैडल गोल आकृति में 35 मिलीमीटर व्यास का होगा। मैडल मानक चांदी का बना होगा। मैडल में सामने की ओर 22 मिलीमीटर ऊंचा राज्य-चिन्ह समुद्रभूत होगा। उसमें पीछे की ओर एक दूसरे को काटती हुई दो तलवारों तथा एक ढाल के ऊपर पांच कोणों वाला एक तारा समुद्रभूत होगा तथा परिमा के साथ-साथ हिन्दी में “रक्षा सुरक्षा कोर मैडल” अंकित होगा। रिबन के लिए मैडल में स्काल रूप में चूल छले की 35 मिलीमीटर चौड़ी फिटिंग होगी। मैडल का एक मुद्राकृत प्रतिरूप निक्षिप्त किया और रखा जायेगा।

तृतीय—मैडल 32 मिलीमीटर चौड़े रेशमी रिबन से वक्षस्थल पर बायीं ओर लटकाया जायेगा। मैडल का रिबन हल्के नीले रंग का होगा तथा उसके दोनों ओर एक मिलीमीटर चौड़ी पीले रंग की छड़ी छारी होगी।

चतुर्थ—मैडल प्रतिवर्ष सेनाध्यक्ष द्वारा प्रदान किया जायेगा। रक्षा सुरक्षा कोर के बै अनायुक्त अफसर और अन्य रैंकों के पदाधिकारी मैडल के पात्र होंगे जिन्होंने कौर में कम से कम सात वर्ष की और रक्षा सुरक्षा कोर तथा सशस्त्र सेनाओं में मिलकर कम-से-कम 15 वर्ष की ऐसी सेवा की हो जिसमें उनका आचरण बराबर बहुत अच्छा रहा हो। मैडल प्रदान किए जाने के साथ 50 रुपये का उपदान भी होगा जो प्रतिवर्ष 25 रुपये की दर से दो वर्षों में दिया जायेगा। मैडल प्रदान करने के प्रयोजनार्थ

केवल ऐसी सेवा पर विचार किया जावेगा जिसको गणना पेशन और उपदान के लिए की जाती है।

पंचम—मैडल प्रति एक हजार अनायुक्त अफसरों/अन्य रैंकों के पदाधिकारियों पर दो के हिसाब से प्रदान किये जाएंगे।

षष्ठिम—सरकार ऐसे अनुदेश देने के लिए सक्षम होगी जो इन अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

रक्षा सुरक्षा कोर मैडल

प्रथम—यह मैडल “रक्षा सुरक्षा कोर मैडल” कहा जायेगा (जिसे इसमें इसके पश्चात् मैडल कहा गया है)।

द्वितीय—मैडल गोल आकृति में 35 मिलीमीटर व्यास का होगा। मैडल कोर्स का बना होगा। मैडल में सामने की ओर 22 मिलीमीटर ऊंचा राज्य-चिन्ह समुद्रभूत होगा। उसमें पीछे की ओर एक दूसरे को काटती हुई दो तलवारों तथा एक ढाल के ऊपर पांच कोणों वाला एक तारा समुद्रभूत होगा तथा परिमा के साथ-साथ हिन्दी में “रक्षा सुरक्षा कोर मैडल” अंकित होगा। रिबन के लिए मैडल में स्काल रूप में चूल छले की 35 मिलीमीटर चौड़ी फिटिंग होगी। मैडल का एक मुद्राकृत प्रतिरूप निक्षिप्त किया और रखा जायेगा।

सूतीय—मैडल 32 मिलीमीटर चौड़े रेशमी रिबन से वक्षस्थल पर बायीं ओर लटकाया जायेगा। मैडल का रिबन हल्के नीले रंग का होगा तथा उसके दोनों ओर 1 मिलीमीटर की चौड़ी पीले रंग की छड़ी धारियां होंगी जिनके मध्य 2 मिलीमीटर का अन्तर होगा।

चतुर्थ—मैडल प्रतिवर्ष सेनाध्यक्ष द्वारा प्रदान किया जायेगा। रक्षा सुरक्षा कोर के बै अनायुक्त अफसर और अन्य रैंकों के पदाधिकारी “रक्षा सुरक्षा कोर मैडल” के पात्र समझे जाएंगे जिन्होंने “उप्रक्रम रक्षा सुरक्षा कोर मैडल” को पाने के लिए पात्रता की शर्तें पूरी कर लो हों, किन्तु उसे प्राप्त न किया हो और पेशन संस्थापन के लिए स्थानान्तरित हो रहे हों या अन्तिम मैडल प्रदान किये जाने के पश्चात् वहां स्थानान्तरित हो गये हों। इस मैडल के पाने वाले उपदान के अधिकारी नहीं होंगे। मैडल प्रदान करने के प्रयोजनार्थ केवल ऐसी सेवा पर विचार किया जायेगा जिसकी गणना पेशन और उपदान के लिए की जाती है।

पंचम—मैदान प्रति एक हजार अनायुक्त अफसरों और अन्य रेंकों के पदाधिकारियों पर दो के हिसाब से प्रदान किया जायेगा।

छठम—सरकार ऐसे अनुदेश देने के लिए सक्षम होगी जो इन अध्यावेशों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

नरोन्द्र सिंह, राष्ट्रपति के सचिव

गृह मन्त्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 8 मई, 1969

गुद्धि-पत्र

सं० 32/10/8-सिव्वंदी (ई०)—गृह मन्त्रालय की दिनांक 22 जून, 1968 की अधिसूचना संख्या 32/2/67-सिव्वंदी (ई०) की वर्तमान कंडिका 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें:—

“उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिये, और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिये जिससे वह सम्बन्धित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलता-पूर्वक न निभा सके। यदि सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के बारे में यह जात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जायेगी। किसी भी उम्मीदवार को, जिसे आयोग मौखिक-परीक्षा के लिये बुलाता है, शारीरिक परीक्षा करानी पड़ेगी।

नोट:—बाद में निराश न होना पड़े इसलिये उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र भेजने से पहले सिविल-सर्जन के स्तर के सरकारी विकित्सा अधिकारी से अपनी आच करवा लें। नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की किस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उसके लिये स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिये, इसके ब्यूरे इन नियमों के परिचार्द 4 में दिये गये हैं। रक्त सेवाओं में विकलांग हुए भूतपूर्व सैनिकों के लिये स्वास्थ्य-स्तर में सेवा (ओं) की आवश्यकताओं के अनुमान छूट दी जायेगी।”

हरीण चन्द्र, अवर सचिव

साक्षा, हृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय (कृषि विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 9 मई 1969

संकल्प

सं० 2-65/66-जिन्स-1—भारत सरकार ने निर्णय किया है कि कृषि विभाग में भारत सरकार के सचिव के स्थान पर, जिन्हें संकल्प संख्या 2-65/66-सी० सी० १ दिनांक 15 दिसम्बर, 1967 के द्वारा परिषद् को पुनर्गठित करते हुए निर्धारित किया गया था, कृषि विभाग में भारत सरकार के अपर सचिव भारतीय नारियल विकास परिषद् के उपाध्यक्ष होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समस्त राज्य मरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और भारत मरकार के समस्त मन्त्रा-

लयों, योजना आयोग, मन्त्रिमण्डल सचिवालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जायें।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में सामान्य जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाए।

ई० प्र० मायूर, उप-सचिव

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 मई, 1969

विषय:—राष्ट्रीय ग्राम उच्च शिक्षा परिषद की स्थायी समिति की कार्यविधि बढ़ाना।

सं० एफ० 1-3/69-य०-4—इस मन्त्रालय की अधिसूचना सं० एफ० 1-8/68-य०-4, दिनांक 12-6-1968 द्वारा यथासंशोधित शिक्षा मन्त्रालय की अधिसूचना सं० एफ० 1-4/66-य०-3, दिनांक 26-4-1966 के जरिए गठित राष्ट्रीय ग्राम उच्च शिक्षा परिषद की स्थायी समिति की कार्यविधि 30 जून, 1969 तक बढ़ाई जाती है। शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय के सचिव और राष्ट्रीय ग्राम उच्च शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष श्री एम० चन्द्रबर्ती, श्री जी० कौ० चन्द्रीरामानी के स्थान पर समिति के अध्यक्ष होंगे।

राम स्वरूप चिट्कारा, उप-शिक्षा सलाहकार

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 30 अप्रैल 1969

संकल्प

सं० 18/38/68-पी० एण्ड पी० सी० (एन० आई० सी०)—इस मन्त्रालय के जन माध्यमों से सम्बन्धित भामलों पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने सम्बन्धी इस मन्त्रालय के संकल्प संख्या 18/38/68-पी० एण्ड पी० सी०, दिनांक 3 दिसम्बर, 1968 में निम्नलिखित मंशोधन किए जाएँ:—

प्रध्यक्ष

(1) “सूचना और प्रसारण मन्त्री” के स्थान पर “सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री” रखा जाए।

संवस्त्र

(2) “सूचना और प्रसारण उप-मन्त्री” के स्थान पर “सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री” रखा जाए।

(3) “सदस्यों” की सूचना में श्री तुषार कान्ति थोष का नाम जोड़ दिया जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समिति के यमी सदस्यों, प्रधान मन्त्री सचिवालय, लोक सभा तथा राज्य सभा नचिवालयों, गृह मन्त्रालय तथा भारत मरकार के अन्य सभी मन्त्रालयों/विभागों को भेजी जाएँ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की सर्वसाधारण की सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

देस राज खंडा, उप-सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT*New Delhi, the 18th November 1968*

No. 26-Pres./69.—The President is pleased to rename the awards of Defence Security Corps Medal Class I and Defence Security Corps Medal Class II, the institution of which was notified in this Secretariat Notification No. 54-Pres./64, dated the 10th July, 1964, as "Unnat Raksha Suraksha Corps Medal" and "Raksha Suraksha Corps Medal", respectively, and to make, ordain and establish the following ordinances which shall be deemed to have effect from the Eighteenth day of November in the year One Thousand Nine Hundred and Sixty Eight :—

UNNAT RAKSHA SURAKSHA CORPS MEDAL

Firstly.—The Medal shall be styled and designated the "UNNAT RAKSHA SURAKSHA CORPS MEDAL" (hereinafter referred to as the medal).

Secondly.—The medal shall be circular in shape and shall be 35 millimetres in diameter. The medal shall be made of standard silver. It shall have embossed on the obverse the State Emblem 22 millimetres in height. On the reverse it shall have embossed a five pointed star over two crossed swords and a shield, and the inscription in Hindi "उन्नत रक्षा सुरक्षा कोर मेडल" along the periphery. The medal shall have a scroll pattern swivel fitting of 35 millimetres width for the riband. A sealed pattern of the medal shall be deposited and kept.

Thirdly.—The medal shall be suspended from the left breast by a silk riband 32 millimetres in width. The riband shall be of light blue, with one vertical stripe of yellow 1 millimetre in width on either side.

Fourthly.—The medal shall be awarded annually by the Chief of the Army Staff. Non-Commissioned Officers and Other Ranks of the Defence Security Corps who have rendered a minimum of seven years' service in the Corps and fifteen years' combined service in the Defence Security Corps and the Armed Forces, distinguished throughout by highly good conduct, shall be eligible for the medal. The medal shall carry with it a gratuity of Rs. 50 to be paid in two years at the rate of Rs. 25 per year. For the purpose of the award only such service as counts for pension, and gratuity shall be taken into consideration.

Fifthly.—The scale of award of the medal shall be 2 per thousand Non-Commissioned Officers/Other Ranks.

Lastly.—It shall be competent for the Government to frame such instructions as may be necessary to carry out the purposes of these Ordinances.

RAKSHA SURAKSHA CORPS MEDAL

Firstly.—The medal shall be styled and designated the "RAKSHA SURAKSHA CORPS MEDAL" (hereinafter referred to as the medal).

Secondly.—The medal shall be circular in shape and shall be 35 millimetres in diameter. The medal shall be made of Bronze. The medal shall have embossed on the obverse the State Emblem 22 millimetres in height. On the reverse it shall have embossed a five pointed star over two crossed swords and a shield, and the inscription in Hindi "रक्षा सुरक्षा कोर मेडल" along the periphery. The medal shall have a scroll pattern swivel fitting of 35 millimetres width for the riband. A sealed pattern of the medal shall be deposited and kept.

Thirdly.—The medal shall be suspended from the left breast by a silk riband 32 millimetres in width. The riband shall be of light blue, with two vertical stripes of yellow 1 millimetre in width and 2 millimetres apart on either side.

Fourthly.—The medal shall be awarded annually by the Chief of the Army Staff. Such of the Non-Commissioned Officers and Other Ranks of the Defence Security Corps as have fulfilled the condition of eligibility for the award of "Unnat Raksha Suraksha Corps Medal", but have not received the same and are under transfer to the Pension Establishment, or have been transferred thereto since the last awards were made, shall be considered for the "RAKSHA SURAKSHA CORPS MEDAL". Recipients of this medal shall not

be entitled to any gratuity. For purposes of the award only such service as counts for pension and gratuity shall be taken into consideration.

Fifthly.—The scale of award of the medal shall be 2 per thousand Non-Commissioned Officers/Other Ranks.

Lastly.—It shall be competent for the Government to frame such instructions as may be necessary to carry out the purposes of these Ordinances.

NAGENDRA SINGH, Secy. to the President

LOK SABHA SECRETARIAT*New Delhi-1, the 1st May 1969*

No. 3(1)ECII-69.—The following members of the Lok Sabha have been elected to serve on the Committee on Estimates for the term beginning on the 1st May, 1969 and ending on the 30th April, 1970 :—

1. Shri K. M. Abraham.
2. Shri S. A. Agadi.
3. Shri B. Anjanappa.
4. Shri R. S. Arumugam.
5. Shri Bedabrata Barua.
6. Shri Brijraj Singh Kotah.
7. Shri Dalbir Singh Choudhary.
8. Shri Hem Raj.
9. Shri Hukam Chand Kachwai.
10. Shri M. Kamalanathan.
11. Shri Bhanudas Ramchandra Kavade.
12. Shri H. Ajmal Khan.
13. Shri Samarendra Kundu.
14. Mahindra Bahadur Raja Kamakhya Prasad Singh Deo.
15. Shri Masuriya Din.
16. Shri Kartik Oraon.
17. Shri Sarjoo Pandey.
18. Shri Manubhai Patel.
19. Shri M. Thirumala Rao.
20. Shri Shashi Bhushan.
21. Shri Ramavtar Shastri.
22. Shri Shiv Kumar Shastri.
23. Shri Nuggehalli Shivappa.
24. Shri Arangil Sreedharan.
25. Shri S. Supakar.
26. Shri G. G. Swell.
27. Shri K. N. Tewari.
28. Shri Gunanand Thakur.
29. Shri Tula Ram.
30. Shri Ramesh Chandra Vyas.

B. K. MUKHERJEE, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**CORRIGENDUM***New Delhi-1, the 8th May 1969*

No. F. 32/10/68-Estt.(E).—In Ministry of Home Affairs notification No. F. 32/2/67-Estt.(E), dated the 22nd June, 1968, for the existing para 18, substitute the following :—

"18. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such physical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for *viva voce* by the Commission may be required to undergo physical examination."

Note :—In order to prevent disappointment, candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of

the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix IV to these rules. For the disabled ex-Defence Services personnel the standards will be relaxed consistent with the requirements of the Service(s)."

HARISH CHANDRA, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

RESOLUTION

New Delhi-1, the 9th May 1969

No. F. 2-65/66-Com.I.—The Government of India have decided that the Additional Secretary to the Government of India, in the Department of Agriculture, shall be the Vice-Chairman of the Indian Coconut Development Council in place of Secretary to the Government of India, Department of Agriculture, as laid down in the Resolution No. 2-65/66-C.C.I., dated the 15th December, 1967 reconstituting the Council.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

I. P. MATHUR, Dy. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES

New Delhi, the 8th May 1969

SUBJECT :—*Standing Committee of the National Council for Rural Higher Education; Extension of the term.*

No. F. 3-1/69-U4.—The tenure of the Standing Committee of National Council for Rural Higher Education constituted *vide* this Ministry's Notification No. F. 1-4/66-U3, dated 26th April, 1966, as amended *vide* notification F. 18/68-U4, dated 12th June, 1968, is hereby extended upto 30th June, 1969. Shri S. Chakravarti, Secretary, Ministry of Education and Youth Services, and Vice-Chairman of the National Council for Rural Higher Education, will be the Chairman of the Committee vice Shri G. K. Chandiramani.

R. S. CHITKARA, Dy. Educational Adviser.

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

(Department of Tourism)

RESOLUTION

New Delhi, the 25th March 1969

No. 5-TH(31)/68.—With the objective of providing the Hotel Industry in the country with the specialised source of financial assistance a Scheme for the grant of loans was sanctioned in Resolution bearing number 5-TH.I(35)/67, dated 19th April, 1968 and published in the Gazette of India No. 18, dated 4th May, 1968.

Paras VII and IX of the Hotel Development Loan instructions annexed to the Resolution be amended as follows:

Amendment (1)

PARA VII. Substitute the following for the existing para VII :—

"RATE OF INTEREST AND ITS PAYMENTS.

The rate of interest on the loans sanctioned under these instructions will be based on the rate charged by the Govern-

ment from industrial undertakings from time to time. At present this rate of interest including the rebate works out to 9 to 9½% per annum depending on the duration of the loan. A rebate of 2½% will be allowed provided that punctual payments of instalments of the loan amount and interest are made and also that the applicant company complies with all other provisions contained in these instructions and the connected documents executed in connection with the loan. In case the applicant company makes any default it shall be liable to pay interest at the rate at which the loan has been advanced both in respect of instalments of amount of the loan and of the interest due and outstanding and no rebate of 2½% will be allowed. When all the arrears are paid, and defaults, if any, rectified, rebate on future punctual payments will be restored.

Interest on the loan will be payable on a half yearly basis commencing from the date on which the amount of loan is drawn by the applicant company until the loan is repaid in full."

Amendment (2)

PARA IX. In para IX of the Instructions delete item (i) and *renumber* the existing items (ii) to (iv) as items (i), (ii) and (iii).

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

A. MITRA, Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

RESOLUTION

New Delhi-1, the 30th April 1969

No. 18/38/68-P&PC(NIC).—The following amendments shall be made in this Ministry's Resolution No. 18/38/68-P&PC, dated the 3rd December, 1968, constituting the Committee of Experts to deal with the matters relating to Mass Media :

Chairman

(i) Substitute "Minister of Information and Broadcasting and Communications" for "Minister of Information and Broadcasting".

Members

(ii) Substitute "Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications" for "Deputy Minister of Information and Broadcasting".

(iii) Add Shri Tushar Kanti Ghosh to the list of "Members".

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to all members of the Committee, the Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats, the Ministry of Home Affairs and all other Ministries/Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

D. R. KHANNA, Dy. Secy.